

प्रेषक,

डॉ०एम०सी० जोशी,

अपर सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत,

बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री,

उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-१

देहरादूनः दिनांक: २३ :मार्च, 2009

विषय:- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में गैर निर्वाचित निकायों के लिए अनुदान धनराशि का आवंटन। (चतुर्थ किश्त)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की निम्न ०३ गैर निर्वाचित नगर पंचायतों को चतुर्थ किश्त हेतु उनके सामने अंकित धनराशि के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये रु० 60444.00 (रु० साठ हजार चार सौ चौवालीस मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रु० में)

क्र० सं०	नगर पंचायत का नाम	राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2008-09 हेतु चतुर्थ किश्त हेतु देय संकमण	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जा रही धनराशि
1-	बद्रीनाथ	250000	230989	19011
2-	केदारनाथ	625000	598633	26367
3-	गंगोत्री	375000	359934	15066
	योग:-	1250000	1189556	60444

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन संकमित की जा रही है-

- (1) संकमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये विल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-1674 / XXVII(1)/2006, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- (2) नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित

धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।
(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-193-नगरपालियां/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि-00-04-राज्य वित्त आयोग द्वारा संरक्षित अन्य अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

मवदीय,

(डॉ०एम०सी० जोशी)
अपर सचिव, वित्त

संख्या:- २२०:(१) / XXVII(१)/2009 एवं तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमौर, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
- 7- वरिष्ठ जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग।
- 8-विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
- 9- निजी सचिव, मारु मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 10-एन०आई०सी०, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा रो,

(डॉ०एम०सी० जोशी)
अपर सचिव, वित्त